International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

औपनिवेशिक भारत में कृषक आन्दोलन

अशोक कुमार
Lect. in History M.A. , NET (History)
G.SSS Gudhan, Rohtak (Haryana)

शोध–आलेख सारः–

भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा हैं। अतः भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हैं इसलिए औपनिवेशिक काल में कृषि व्यवस्था का प्रभावित होना स्वाभाविक था। प्राचीन कृषि व्यवस्था नवीन प्रशासनिक ढ़ाचे के अधीन धीरे–2 टूट गई । कृषि व्यवस्था में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कर अत्यधिक करने से किसानों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई । सरकारी कर तथा जमीनदारों का भाग अत्यधिक होने के कारण कृषक साहूकारों तथा व्यापारियों के चुंगल में फंस गए। कृषकों क`अब दो दुश्मन हो गए थे जिनसे निपटना बहुत ही मुश्किल था एक अंग्रेज तथा दूसरा साहूकार उन्नीसवीं शताब्दी में कृषकों का गुस्सा विद्रोहों तथा प्रतिरोधी के रूप में प्रकट हुआ और देश के विभिन्न भागों में समय–समय पर कृषकों ने अंग्रेजी हुकूमत और पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज बुलन्द की और एकत्रत होकर अपना शेष विद्रोह के रूप में प्रकट किया। उनके विरोध का प्रमुख कारण भूमि कर बढ़ाने , बेदखली और साहूकारों की ब्याजखोरी प्रमुख थे। कृर्ष वर्ग में पूर्ण जागृति और सुव्यवस्थित संगठन न होने के कारण कृषकों के विद्रोह ने राजनैतिक रूप धारण नहीं किया परन्तु 20वीं शताब्दी में वर्ग जागृति आई और अनेक किसान सभाओं की स्थापना हुई।

मूल शब्दः–

अर्थव्यवस्था , कृषि प्रधान , साहूकार , प्रशासनिक ढ़ांचा , भूमिकर , ब्याजखोरी , वर्ग जागृति ।

आकाल तथा कृषकः–

19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में बार–2 अकाल पड़े तथा भूख से लाखों की संख्या में किसान तथा अन्य गरीब लोग मारे गए। इस काल में भारत के अलग–2 भागों में 24 छोटे–बड़े अकाल पड़े जिनमें लगभग 2 करोड़ 85 लाख व्यक्ति मर गए। 1876–78 , 1896–97 तथा 1899–1900 के भीषण अकाल से यह स्पष्ट हो गया कि शोषण से भरपूर भूमिकर नीति का क्या अंजाम होता हैं। सरकार द्वारा स्थापित 1880,1898 और 1901 के अकाल आयोगों से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार के राहत कार्य का उद्देश्य परोपकार नहीं बल्कि सम्पत्ति की संस्था को बनाए रखना हैं।

1855–56 का संथाल विद्रोहः–

बड़ा भूम , मानभूम , हजारी बाग , मिदिनापुर ,वीरभूमि इत्यादि प्रदेश में रहने वाले संथाल शांतिप्रिय तथा नम्र स्वभाव के लोग थे। लगातार मेहनत करके इन्होंने खाली पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाया परन्तु अंग्रेजों की 1793 ई0 की स्थाई भूमि कर व्यवस्था के अनुसार अब वह जमींदारों की हो गई थी। जमींदारों के अत्यधिक शोषण के कारण इन्होंने भूमि को छोड़ दिया और राजमहल की पहाड़ियों में शरण ली तथा पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों को काट कर बड़े कठिन परीश्रम से कृषि योग्य भूमि तैयार की परन्तु जमींदारों ने इस भूमि पर भी स्वामित्व का दावा किया जिसके कारण संथालों के सब्र का बांध टूट गया दो भाईयों सिद्ध व कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने उत्तरी भारत के साहूकार लोग

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

तथा अंग्रेज अधिकारियों के विरूद्ध 1855 में विद्रोह कर दिया[1] और यह घोषणा कर दी कि ''वें देश को अपने अधिकार में ले लेंगे तथा अपनी सरकार स्थापित कर देंगे।'' संथालों ने कम्पनी के शासन की समाप्ति और अपने सुबेदारों को शासन की घोषणा कर दी। अंग्रेजों की तरफ से सैनिक कार्यवाही की गई परन्तु मेजर बर्रो[2] के अधीन एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को अपमान जनक मात खानी पड़ी परन्तु 1856 में सिंधु व कान्हू को बन्दी बना लिया गया । विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबा दिया गया परन्तु सरकार को अलग संथाल परगने बनाकर उनके रोष को शांत किया गया।

1857 के विद्रोह में किसानों की भूमिका :–

इस विद्रोह में किसानों ने अलग–2 स्थानों पर अलग–2 भूमिका निभाई। अवध तथा पश्चिमी यू0पी0 में किसानों ने जमीनदारों के क्रूर व्यवहार को भूलाकर अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह में सहयोग दिया[3]। परन्तु कुछ जगह पर किसान इस विद्रोह के प्रति नीरस रहे। अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह में शामिल होने वाले प्रदेशों के किसानों पर अतिरिक्त दण्ड लागू किया।

बंगाल में नील विद्रोह , 1860:–

ये विद्रोह अंग्रेजी भू–स्वामियों के विरूद्ध किया गया जो कि अपनी जागीरों में किसानों पर अत्याचार करते थे। इस विद्रोह में विद्रोहियों की जमींदारों , धनी कृषकों, साहूकारों तथा ग्रामीणों की सहानुभूति प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेज साहूकारों ने अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जो लाभप्रद नहीं थी। इसके विरोध में 1860 में बारासात उपविभाग तथा पावना न दिया जिलों के समस्त कृषकों ने , भारतीय इतिहास की प्रथम कृषकों की हड़ताल कर दी[4]। शीघ्र ही यह विरोध ढाका ,मालदा , राजशाही , दीनाजपुर तथा बंगाल के अन्य प्रदेशों में फैल गया। और किसानों की बात मानी गई अब वे नील उगाने के लिए बाध्य नहीं थे।1860 में एक नील आयोग नियुक्त कर दिया गया जिसने अपनी रिपोर्ट में किसानों का पक्ष लिया और अंग्रेज भूमिपति कालांतर में बंगाल छोड़कर बिहार तथा उत्तर–प्रदेश में चले गए।

1875 के दक्षिण के विद्रोह:–

ये विद्रोह मुख्यतः गुजराती तथा मारवाड़ी साहूकारों के विरूद्ध किए गए। मारवाड़ी साहूकार लालची थे वे अपने लेखों में हेरा–फेरी करके अनपढ़ और भोले किसानों से झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान ले लेते थे जिसके कारण बाद में धोखे से किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया जाता था[5]। यह विद्रोह 1874ई0 में सिरूर तालुका में तब प्रारम्भ हुआ जब साहूकार कल्लूराम ने 150रु0 के झूठे ऋण के लिए बाबा साहिब देशमुख का मकान गिरा दिया और उसे बेदखल कर दिया । इससे ग्रामवासियों को गुस्सा आ गया और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। पुलिस तथा सेना ने क्रूरता से विद्रोह का दमन किया 1875 के अन्त तक 1000 से अधिक लोग बन्दी बनाए जा चुके थे। सरकार ने एक 'ढक्कन उपद्रव आयोग' नियुक्त किया , जिसे उपद्रव के कारणों का पत्ता लगाना था। कृषकों की अवस्था को सुधारने के लिए '1879 में कृषक राहत अधिनियम' पारित किया गया जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि कृषकों द्वारा ऋण न चुकाने पर उसे बन्दी नहीं बनाया जा सकता था।

पंजाबी किसानों का असंतोष तथा पंजाब भूमि अन्याक्रामण अधिनियम:–

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

पंजाब क्षेत्र में किसानों की भूमिका अकृषकों वर्ग के पास स्थानांतरित होना कहीं बंगाल तथा महाराष्ट्र की तरह विद्रोह का कारण न बन जाए इसलिए 1895 में भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को लिखा कि भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए। 'पंजाब भूमि अन्याक्रामण अधिनियम 1900' एक प्रयोग के रूप में पारित किया गया[6]। इसका अभिप्राय यह था कि अगर यह प्रयोग पंजाब में सफल हुआ तो भारत के अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत , पंजाब के लोगों को तीन भागों में बांट दिया गया , कृषक , कानून द्वारा स्थापित कृषक (जो वास्तव में किसान नहीं थे परन्तु भूमि के प्रति विशेष लगाव था) तथा शेष जनता जिसमें साहूकार भी शामिल थे। इस अधिनियम में प्रथम वर्ग के लोगों को दूसरे तथा तीसरे वर्ग के लोगों को भूमि बेचने तथा गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कृषकः–

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रारम्भिक काल से ही कृषकों के उत्थान तथा भलाई के लिए कभी कोई मांग नहीं रखी। परन्तु देश की निर्धनता को दूर करने के सुझावों में कांग्रेस द्वारा भूमिकर कम करना तथा स्थाई भूप्रबंध पूरे देश में लागू करना आदि मांगें तो रखी लेकिन किसानों को लेकर मुख्य मांग या कार्यक्रम नहीं रखा[7]।श्री आर0 सी0 दत्त ने जो पत्र लार्ड कर्जन के नाम भारतीय अकाल के विषय में लिखे थे , उनको पढ़ने से यह मालूम हो जाता हैं कि कांग्रेस जानबूझ कर या अनजाने में भूमिपतियों की बात करती थी , कृषकों की नहीं।

गाँधी जी तथा किसान आन्दोलनः–

भारतीय राजनीति में गांधी जी के आगमन से देश को नई दिशा तथा चेतना मिली। क्योंकि वह आन्दोलन का स्तर बड़ा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने गरीब लोगों तथा किसानों को भी आन्दोलन में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया[8]।

चम्पारण तथा खेड़ा सत्याग्रहः–

बिहार के चम्पारण जिले में यूरोपीय नील उत्पादक भारतीय किसानों को अनेक प्रकार के शोषण करते थे , जैसे बंगाल में था। महात्मा गांधी ने राजेन्द्र प्रसाद की सहायता से वास्तविक स्थिति की जांच की और पाया कि बिहारी कृषक अत्यंत शोषित हैं।गांधी जी ने किसानों को अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन या सत्याग्रह की शिक्षा दी[9]। बिहार सरकार ने गांधी जी को गिरफतार कर लिया और एक जांच समिति नियुक्त कर दी जिसमें गांधी जी स्वयं एक सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट में 'चम्पारण कृषि अधिनियम' पारित किया गया जिसमें नील उत्पादकों द्वारा विशेष प्राप्ति बंद कर दी गई।

खेड़ा आन्दोलन 1918 में बम्बई सरकार के विरूद्ध किया गया। सूखे के कारण यहां किसानों की फसले नष्ट हो गई और सरकार ने कर को क्रूरता से वसूल करना शुरू कर दिया । फसल खराब होने के कारण किसान भूमिकर देने में असर्मथ थे अतः गांधी जी के समर्थन से किसानों ने सत्याग्रह किया[10] और मजबूर होकर अंग्रेंजी हुकूमत को कर में छूट देनी पड़ी । परन्तु जूडिथ ब्राउन जैसे लोगों ने यह कहा हैं कि सरकार ने कर का लगभग 93% फिर भी वसूल कर लिया।

1921 का मोपला विद्रोहः–

दक्षिणी मालाबार के मुस्लमान पट्टेदारों तथा खेतीहर किसानों की प्रायः मोपला कहते थे। आरम्भ में ये लोग गरीब हिन्दू थे जो बाद में मुस्लमान बन गए थे। ये लोग

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

हिन्दू जमीनदारों के बंधुआ मजदूर थे। 19वीं शताब्दी में मोपलाओं की कृषि सम्बन्धी शिकायतें बढ़ गई जिनमें अत्यधिक मालगुजारी , पट्टेदारी की असुरक्षा , नवीनीकरण के समय अत्यधिक धन की मांग तथा समय –2 पर जमींदारों की नाजायत कर वसूली शामिल थी। 1921[11] में मोपला विद्रोह के दो कारण प्रमुख थे। एक तो मोपलाओं पर जमीनदारों का अत्याचार और दूसरा , अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां थी। मोपला किसान अंग्रेजों की नीतियों से बहुत परेशान ये क्योंकि अंग्रेजी सरकार साहूकारों तथा पूंजीपतियों का पक्ष लेती थी। विद्रोह का तात्कालिक कारण एरनाड तालुकि के जिला मेजिस्ट्रेट ने जुटाया। उन्होंने 20 अगस्त 1921 को तिरूरांगड़ी में स्थित एक मस्जिद में घुसकर अली मुसालियार को बन्दी बनाने का प्रयत्न किया । शीघ्र ही यह बात पुरे तालुकों में फैल गई जिसके फलस्वरूप रास्ते रोक लिए गए , अनेक अंग्रेजों को जान से मार दिया गया। तार लाईने तथा रेलवे ट्रक उखाड़ दिए गए।

सेना ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया लगभग 2337 मोपला मारे गए तथा 1652 घायल हुए , ये सरकारी आकड़े , जबकि गैर सरकारी अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 तक थी तथा 3000 मोपलाओं की आजीवन काले पानी की सजा दी गई।

किसान सभाओं का गठन :–

साम्यवादी तथा वामपन्थी दलों ने किसानों में संगठन की भावना को प्रबल किया और किसान सभाओं के गठन में विशेष भूमिका निभाई। 1920 के दशक में बंगाल , पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किसानों के अनेक संगठन बने। 1928 में 'आंध्र प्रान्तीय रैयत सभा ' बनी परन्तु अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल , 1936[12] को लखनऊ में हुआ। किसान सभा का उद्देश्य दिलाना , भूमिकर कम करना , सिंचाई के साधनों का विकास करवाना तथा शोषण वाली नीतियों को बदलवाना था।

प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारें तथा कृषक आन्दोलन :–

जब 1937 में लोकप्रिय सरकारे बनी तो कृषकों को इस सरकार से बहुत आशाएं थी परन्तु किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए बिहार विधान सभा के अधिवेशन से पहले दिन 23,000 किसान विधानसभा भवन के सामने एकत्रित हो गए उनके नारे थे ''हमें पानी दो हम प्यासे हैं , हमें रोटी दो हम भूखे हैं , हमारे सभी कृषि ऋण छोड़ दो , हमें जमींदारों के शोषण से बचाओ।''

अतः सरकार ने बाकाश्त भूमि अधिनियम तथा बिहार मुजारा अधिनियम को लागू किया जिससे किसानों को कुछ राहत मिली।

भारत स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या पर कृषक आन्दोलनः–

हमारी स्वतन्त्रता के पूर्व 10 वर्षों में तीन प्रमुख कृषक आन्दोलन चलेः, तेभागा आन्दोलन (बंगाल) , तेलंगाना आन्दोलन (हैदराबाद) तथा वली विद्रोह (पश्चिमी भारत)। मूल रूप से ये सभी आन्दोलन ठेकेदारों , साहूकारों, अंग्रेज अधिकारियों , भूमिपतियों , जमींदारों तथा धनी किसानों के विरूद्ध थे। इन आन्दोलनों के द्वारा शोषित किसानों ने अपने जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं की सुरक्षा की मांग की।

स्वतंत्रता के समय किसनों को यह विश्वास था कि अब उनके जीवन की अंधियारी रात का अंत हो गया हैं और अब उनकी उचित मांगें स्वीकार हो जाएगी लेकिन अब भी किसानों के अनेक कठिनाईयों से रूबरू होना पड़ता हैं।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

संदर्भ सूची:–

1. Social and Cultural History of India Since 1556 , N.Jayapalam Page-173
2. Pratiyogita Darpan , August-2007 , Page – 246
3. Modern South Asia : History , Culture ,Political , Economy Sugata Bose , Ayesha Jalal -2017
4. Peasant Labour and Colonial Capital : Rural Bengal Since 1770 , Page-155
5. Rural Political Protest in Western India , Livi Ro drigues, Page-XI
6. Pratiyogita Darpan , Optional Subject , Indian History , Modern India , Page – 168
7. Peasants in India's Non-violent Revolution Pratice and theary Mridula Mukherjee , Page -337
8. Gandhi , David Arnol , Page -74
9. Satyagraha In Champarn , Dr. Rajendra Prasad , Page-8
10. Glimpses of Indian National Movement , Abel M-2005 , Page-136
11. India's Struggle for Freedom : An Album , Page -114
12. Land , Labour and Power: Agrarian Crisis and the State in Bihar ……. , Usha Jha , Page-26